

UPGK010085632025

न्यायालय : सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर।सेशन केस संख्या- 2006/2025

उत्तर प्रदेश राज्य बनाम श्रीभागवत व अन्य।

अपराध संख्या- 612/2024

धारा- 115 (2), 352, 351 (2), 351 (3),

333, 110 भारतीय न्याय संहिता,

थाना- चौरीचौरा, जनपद-गोरखपुर।

03.12.2025

सत्र परीक्षण की पत्रावली आज प्रार्थना-पत्र कागज संख्या- 6 ख पर आदेश हेतु नियत है।

पूर्व की तिथि पर प्रार्थना-पत्र कागज संख्या- 6 ख पर आवेदकगण/ अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता तथा उत्तर प्रदेश राज्य की तरफ से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, दाण्डिक के विद्वतापूर्ण तर्कों को सुना जा चुका है।

प्रार्थना-पत्र कागज संख्या- 6 ख के माध्यम से आवेदकगण/अभियुक्तगण श्रीभागवत, लालमुनी देवी, दिलबहादुर व गुलाब के द्वारा यह निवेदन किया गया है कि अपराध संख्या- 612/2024, धारा- 115 (2), 352, 351 (2), 351 (3), 333, 110 भारतीय न्याय संहिता, थाना- चौरीचौरा, जनपद-गोरखपुर के प्रकरण में उसे उन्मोचित किया जावे।

प्रार्थना-पत्र कागज संख्या- 6 ख में आवेदकगण/अभियुक्तगण के द्वारा यह कथन किया गया है कि वे निर्दोष हैं। आहत गुड़िया देवी, मीरा देवी, शान्ति देवी व रीमा देवी को आयी उपहतियों को चिकित्सक द्वारा साधारण प्रकृति का होना बताया गया है। दौरान विवेचना विवेचक द्वारा आवेदकगण/अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा- 110 भारतीय न्याय संहिता के अपराध का न होने पर भी जबरदस्ती झूठा आरोप लगाकर आरोप-पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया है। आवेदकगण/अभियुक्तगण के विरुद्ध सम्पूर्ण केस डायरी व विवेचना में ग्रहण साक्ष्यों के आधार पर आवेदकगण/अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा-110 भारतीय न्याय संहिता का अपराध गठित नहीं होता है।

उत्तर प्रदेश राज्य की तरफ से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, दाण्डिक द्वारा प्रार्थना-पत्र कागज संख्या- 6 ख में उल्लिखित तथ्यों का घोर विरोध किया गया तथा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि विवेचक द्वारा विवेचना के दौरान अभियुक्तगण की कथित अपराध में सक्रिय भागिता एवम् भूमिका पाते हुए उनके विरुद्ध आरोप-पत्र न्यायालय में विचारण हेतु प्रेषित किया गया है। विवेचक के समक्ष दिये गये कथन में साक्षीगण के द्वारा

कथित अपराध में अभियुक्तगण की संलिप्तता के बिन्दु पर स्पष्ट कथन किया गया है। उनके द्वारा प्रार्थना-पत्र कागज संख्या- 6 ख आधारहीन एवम् बलहीन होना बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

दिनांक 11.11.2024 को समय करीब 12:00 बजे ग्राम विलारी मठिया, अन्तर्गत थाना- चौरीचौरा, जनपद- गोरखपुर में घटित घटना की प्राथमिकी, जिसमें प्रथम सूचनाकर्त्री रीमा देवी के द्वारा स्वयं को तथा मीरा देवी, गुड़िया व शान्ति देवी को अभियुक्तगण के द्वारा लाठी-डण्डा, राड व कुल्हाड़ी से मार-पीटकर गम्भीर उपहति पहुँचाने, और भट्ठी-भट्ठी गालियाँ देते हुए जान से मारने की धमकी दिये जाने का कथन किया गया था।

दिनांक 11.11.2024 को समय 18:26 बजे थाना- चौरीचौरा में अपराध संख्या- 612/2024 पर भारतीय न्याय संहिता धारा- 191 (2), 115 (2), 352, 351 (2), 351 (3), 333, 110, 304 के अपराध के अन्तर्गत आवेदकगण/अभियुक्तगण के विरुद्ध पंजीकृत की गयी तथा विवेचनोपरान्त विवेचक द्वारा आवेदकगण/अभियुक्तगण के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा- 115 (2), 352, 351 (2), 351 (3), 333, 110 के अपराध के अन्तर्गत आरोप-पत्र न्यायालय में विचारण हेतु प्रेषित किया गया।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा- 180 के अन्तर्गत विवेचक द्वारा प्रथम सूचनाकर्त्री/आहत रीमा पासवान, आहत मीरा देवी, आहत गुड़िया, आहत शान्ति देवी, महातम व मधुरानी आदि का साक्ष्य लेखबद्ध किया गया है। प्रथम सूचनाकर्त्री/आहत रीमा पासवान के द्वारा विवेचक के समक्ष इस आशय का कथन किया गया है कि झगड़े के दौरान लालमुनी देवी, श्रीभागवत, दिलबहादुर, गुलाब, बबिता व पुष्पा द्वारा भट्ठी-भट्ठी गाली-गुप्ता देते हुए इसको व इसके परिवार के लोगो को घर के सामने लाठी-डण्डा से मारा-पीटा गया। जब ये लोग बचने के लिए घर में घुस गये, तो उक्त लोगो द्वारा घर में घुस कर मारा-पीटा गया, जिसमे मीरा देवी, गुड़िया, नवनाथ व शान्ति देवी को चोट आयी। मारपीट करने के बाद सभी लोग जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गये। उपरोक्त आशय का ही कथन अन्य साक्षियों द्वारा भी विवेचक के समक्ष किये गये हैं।

चिकित्सकीय परीक्षण आख्या में आहत मीरा देवी के शरीर पर कुल 05 उपहतियाँ आना उल्लिखित हैं, जिनमे से उपहति संख्या- 01 फटे हुए घाव के रूप में उसके सिर के पेराइटल क्षेत्र में मौजूद था तथा 03 अन्य उपहतियाँ खरांश की व एक उपहति दर्द की शिकायत की थी। आहत रीमा देवी के चिकित्सकीय परीक्षण आख्या में उसके शरीर पर कुल 06 उपहतियाँ आना उल्लिखित है, जिनमे से 04 उपहतियाँ निलगू निशान की व एक उपहति खरांश की तथा एक उपहति दर्द की शिकायत की थी। आहत गुड़िया के चिकित्सकीय परीक्षण आख्या में कुल 04 उपहतियाँ आना वर्णित है, जिनमे से उपहति संख्या- 01 व 03 निलगू निशान के रूप में, उपहति संख्या- 02 खरांश के रूप में हैं, तथा उपहति संख्या- 04 बाये जांघ में दर्द की शिकायत थी। आहत शान्ति देवी के चिकित्सकीय परीक्षण आख्या में कुल 03 उपहतियाँ आना वर्णित हैं, जिनमे से पहली उपहति उसके माथे पर फटे हुए घाव के रूप में मौजूद थी तथा दो अन्य उपहतियाँ निलगू निशान की थी।

विवेचक द्वारा विवेचना के दौरान संकलित किये गये साक्ष्य के आधार पर आवेदकगण/अभियुक्तगण के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा- 115 (2), 352, 351 (2), 351 (3), 333, 110 के अन्तर्गत आरोप-पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया। न्यायालय द्वारा आवेदकगण/अभियुक्तगण के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला पाते हुए दिनांक 18.02.2025 को संज्ञान लिया गया है। स्वीकृत रूप से आवेदकगण/अभियुक्तगण के विरुद्ध लिये गये संज्ञान आदेश दिनांकित 18.02.2025 को आवेदकगण/अभियुक्तगण द्वारा कहीं चुनौती नहीं दी गयी है।

प्रस्तुत अभियोग में आवेदकगण/अभियुक्तगण प्राथमिकी में नामित हैं तथा उनके विरुद्ध कथित घटना की तिथि को प्रथम सूचनाकर्त्री रीमा देवी तथा मीरा देवी, गुड़िया व शान्ति देवी को लाठी-डण्डा, राड व कुल्हाड़ी से मारपीटकर उपहतियाँ पहुँचाने तथा गाली-गलौज किये जाने व जान से मारने की धमकी देने का अभ्यारोपण अन्तर्ग्रस्त है। प्रथम सूचनाकर्त्री द्वारा प्रस्तुत लिखित तहरीर के आधार पर थाना- चौरीचौरा में अपराध संख्या- 612/2024 पर भारतीय न्याय संहिता धारा- 191 (2), 115 (2), 352, 351 (2), 351 (3), 333, 110, 304 के अपराध के अन्तर्गत अभियुक्तगण के विरुद्ध प्राथमिकी पंजीकृत की गयी और सम्यक् विवेचनोपरान्त विवेचक द्वारा भारतीय न्याय संहिता की धारा- 115 (2), 352, 351 (2), 351 (3), 333, 110 के अन्तर्गत अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप-पत्र विचारणार्थ न्यायालय में प्रेषित किया गया। इस स्तर पर घटना के स्वरूप, अभियुक्तगण की सक्रिय सहभागिता, चोटों की प्रकृति आदि अन्य उठाये गये बिन्दुओं पर निश्चायक विनिश्चयन किये जाने से अभियोग में मिनी ट्रायल का स्वरूप ग्रहण हो जायेगा। आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने मौखिक तर्क में विरोधाभास एवं अन्य तथ्य के बावत जो उन्मोचन का आधार बताया गया है, वह आधार/तर्क विचारण के दौरान निर्णय के स्तर पर देखा जाना है। आरोप के स्तर पर मात्र प्रथम दृष्टया मामला ही देखा जाना होता है। आवेदकगण/अभियुक्तगण के विरुद्ध पत्रावली पर प्रथम दृष्टया मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य उपलब्ध है।

यहाँ यह भी उल्लिखित किया जाना समीचीन है कि इस प्रक्रम पर मामले में साक्ष्य की विवेचना गुण-दोष के आधार पर की जानी अपेक्षित नहीं है। अपितु अभियोजन द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर यह समाधान किया जाना है कि मामले में अग्रिम कार्यवाही के लिए आधार पर्याप्त है या नहीं, जैसा कि उपरोक्त उद्धरित अभियोजन कथानक एवम् केस डायरी में उपलब्ध साक्ष्य से यह परिलक्षित है कि आवेदकगण/अभियुक्तगण के विरुद्ध प्रथम दृष्टया भारतीय न्याय संहिता की धारा- 115 (2), 352, 351 (2), 351 (3), 333, 110 का आरोप लगाये जाने हेतु प्रथम दृष्टया सामग्री उपलब्ध है। आवेदकगण/अभियुक्तगण को कथित अपराध से इस स्तर पर उन्मोचित किये जाने का कोई ठोस एवम् न्यायोचित आधार विद्यमान नहीं है।

आरोप विरचित किये जाने के संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय की पूर्ण पीठ ने अपने न्यायिक दृष्टान्त सुप्रीन्टेंडेंट एण्ड रिमेंडेंसर ऑफ लीगल अफेयर्स, वेस्ट बंगाल

विरुद्ध अनिल कुमार भुन्जा ए०आई०आर० 1980 सु० को० 52 (एफ०बी) में यह अवधारित किया है कि—

“At this stage, as was pointed out by this Court in *State of Bihar v. Ramesh Singh*’ AIR 1977 SC 2018, the truth veracity and effect of the evidence which the prosecutor proposes to adduce are not to be meticulously judged. The standard of test, proof and judgment which is to be applied finally before finding the accused guilty or otherwise is not exactly to be applied at the stage of Section 227 or 228 of the Code of Criminal Procedure, 1973. At this stage, even a very strong suspicion founded upon materials before the Magistrate, which leads him to form a presumptive opinion as to the existence of the factual ingredients constituting the offense alleged may justify the framing of charge against the accused in respect of the commission of that offence.”

उक्त न्यायिक दृष्टान्त के अनुसार आरोप विरचित किये जाने के प्रक्रम पर साक्ष्य की सत्यता तथा प्रकरण की सूक्ष्मता से विवेचना करने की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रक्रम पर यदि अभियुक्त के द्वारा अपराध किये जाने के सन्दर्भ में सन्देह भी उत्पन्न होता है तब भी अभियुक्त के विरुद्ध आरोप की विरचना की जा सकती है।

माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त स्टेट ऑफ एम०पी० विरुद्ध एस०बी० जौहरी (ए०आई०आर० 2000 सु० को० 665) में यह अवधारित किया गया है कि—

“It is settled law that at the stage of framing the charge, the court has to prima facie consider whether there is sufficient ground for proceeding against the accused. The Court is not required to appreciate the evidence and arrive at the conclusion that the materials produced are sufficient or not for convicting the accused. If the Court is satisfied that a prima facie case is made out for proceeding further then a charge has to be framed.”

इसी प्रकार **दाण्डिक अपील संख्या-1578/2008 संघी ब्रदर्थ (इंदौर) प्रा०लि० बनाम संजय चौधरी व अन्य निर्णीत दिनांकित 03.10.2008** के अपने सम्मानित निर्णय के पैरा-11 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने उल्लिखित किया है कि— “The present case is not one where the High Court ought to have interfered with the order of framing the charge. As rightly submitted by learned counsel for the appellant, even if there is a strong suspicion about the commission of offence and the involvement of the accused, it is sufficient for the court to frame a charge. At that stage, there is no necessity of formulating the opinion about the prospect of conviction. That being so, the impugned order of the High Court cannot be sustained and is set aside. The appeal is allowed.”

विधि व्यवस्था **महाराष्ट्र राज्य बनाम सोमनाथ थापा 1996 क्रिमिनल लॉ जनरल 2448 (सुप्रीम कोर्ट)** में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि यह उपधारणा करने के लिये आधार है कि अभियुक्त ने अपराध कारित किया है, तो न्यायालय न्यायोचित रूप से तो यह कह सकती है कि प्रथम दृष्टया उसके विरुद्ध मामला बनता है अर्थात् यदि अभिलेख पर सामग्री के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि अपराध कारित किये जाने की सम्भावना बनती है, तो आरोप तैयार करने का मामला बनता है। दूसरे शब्दों में यदि न्यायालय यह समझती है कि अभियुक्त ने अपराध कारित किया होगा, तो वह आरोप तैयार कर सकता है, किन्तु दोषसिद्ध करने के लिये यह निष्कर्ष आवश्यक है कि अभियुक्त ने अपराध कारित किया। यह स्पष्ट है कि आरोप विरचित किये जाने के प्रक्रम पर अभिलेख पर

उपलब्ध सामग्री का सम्भाव्यतापरक मूल्यांकन होना चाहिए। अभियोजन द्वारा अभिलेख पर लाई गयी सामग्री को उस प्रक्रम पर सत्य मानकर स्वीकार करना चाहिए। विधि का यह सुस्थापित एवं मान्य सिद्धान्त है कि आरोप गम्भीर सन्देह के आधार पर भी विरचित किया जा सकता है। विधि व्यवस्था **हीरा लाल तथा अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य तथा अन्य 2017 (2) जू०क्रि०के० 1522** के अपने सम्मानित निर्णय में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने कहा है कि आरोप बनाते समय न्यायालय को यह देखना आवश्यक नहीं है कि क्या उपलब्ध साक्ष्य दोषसिद्धि के लिये पर्याप्त है। इस स्तर पर यही देखा जाना पर्याप्त है, कि जिससे यह अन्देशा निकले कि क्या अभियुक्त ने तथाकथित अपराध कारित किया है या नहीं? इसी प्रकार विधि व्यवस्था **राजपाल व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य 2017 (2) जे०क्रि०के० 1797** के अपने सम्मानित निर्णय में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने कहा है कि आरोप निर्मित करते समय केवल अभिलेख पर उपलब्ध प्रथम दृष्टया साक्ष्य को अंकलित किया जाना चाहिए भले ही प्रबल सन्देह दृष्टिगत होता है फिर भी इस स्तर पर आरोप मुक्ति के लिये अपर्याप्त है।

पलविन्दर सिंह प्रति बलविन्दर सिंह 2009 (65) ए.सी.सी. 399 (सुप्रीम कोर्ट) तथा स्टेट एन.सी.टी. ऑफ दिल्ली प्रति शिव चरन बंसल (2020) 2 एस.सी.सी 290 के मामलों में माननीय न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि—

Charge can be framed also on the basis of strong suspicion. Marshalling and Appreciation of evidence is not in the domain of the court at that point of time.

अतएवं सम्पूर्ण तथ्यों एवम् परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आवेदकगण/अभियुक्तगण को भारतीय न्याय संहिता की धारा— 115 (2), 352, 351 (2), 351 (3), 333, 110 के अपराध से उन्मोचित किये जाने का कोई औचित्य नहीं है।

निष्कर्षतः आवेदकगण/अभियुक्तगण की तरफ से प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र कागज संख्या— 6 ख निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदकगण/अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत उन्मोचन प्रार्थना-पत्र कागज संख्या— 6 ख निरस्त किया जाता है।

अभियुक्तगण के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा— 115 (2), 352, 351 (2), 351 (3), 333, 110 के अपराध के अन्तर्गत आरोप की विरचना हेतु पत्रावली आगामी दिनांक 08.12.2025 को प्रस्तुत हो। उक्त तिथि को अभियुक्तगण न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हों।

दिनांक/गोरखपुर

03 दिसम्बर, 2025

(राज कुमार सिंह)

सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर।

J.O Code- UP1889